28-10-26 VNS PG-9 DESH VIDESH-ALLA.qxd 27-10-2026 22:44 Page 1

रेल मंत्री ने की चक्रवात 'अर्नब' से निबटने की तैयारियों की समीक्षा

नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने २८ अक्टूबर २०२६ को सम्भावित रूप से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अर्नब' से निबटने की तैयारियों की समीक्षा की। दक्षिण तटीय रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे में सुरक्षा प्रोटोकाल और त्वरित बहाली (रेस्टोरेशन) की व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। इसके तहत, चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले इलाकों में लगभग ६०० किलोमीटर रेलवे ट्रैक की कड़ी निगरानी की जा रही है।

जोनल, डिविजनल और रेलवे बोर्ड स्तरों पर 'वार रूम' सक्रिय हैं, जहां चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं और किसी भी तरह की रुकावट आने पर तुरंत काररवाई करने के लिए आपातकालीन संसाधन तैयार रखे गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम डिवीज़न सहित संवेदनशील इलाकों में लगभग ६०० किलोमीटर रेलवे ट्रैक की कड़ी निगरानी की जा रही है। आपातकालीन बहाली कार्यों में मदद के लिए, मरम्मत का सामान ले जाने वाले वैगन कृष्णा नहर, बिट्रागुंटा, मामिदिपुडी, विशाखापत्तनम, पलासा और पोंडुरू में तैनात किए गए हैं। डीजल लोकोमोटिव, पावर यूनिट और एम्बुलेंस प्रमुख जंक्शनों पर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर तुरंत काम शुरू करने के लिए, अर्थमूवर, पेड़ काटने वाली मशीनें और मरम्मत के औजार थोड़ी-थोड़ी दूरी पर तैनात किए गए हैं। हर घंटे मौसम की निगरानी की जा रही है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जगहों पर तैनात किया गया है। आपातकालीन स्थितियों में मिलकर काम करने के लिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

एआई+ स्मार्टफोन के चुनिंदा माडल्स 15 नवंबर से होंगे महंगे

प्रयागराज- एआई+ स्मार्टफोन ने 15 नवंबर, 2026 से अपने पोर्टफोलियो के चुनिंदा मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। खासकर कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में लागत का दबाव लगातार बना हुआ है। एआई+ स्मार्टफोन अब तक इस दबाव के असर का आकलन करते हुए ग्राहकों के लिए फोन की कीमतें किफायती बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। हालाँकि, बढ़ती लागत के चलते कंपनी ने कीमतों में एक बार फिर सीमित बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, ताकि फोन की कीमतों को किफायती बनाए रखने के साथ ग्राहकों को बेहतर अनुभव भी दिया जा सके। कीमतों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में, ग्राहक 14 नवंबर तक अपने पसंदीदा एआई+ स्मार्टफोन मौजूदा कीमतों पर खरीद सकते हैं।नई कीमतों के तहत एआई+ पल्स 2 एफई, पल्स 2, नोवा 2 5जी, नोवा 2 नियो 5जी, नोवा 2 पावर 5जी, नोवा 2 प्रो 5जी और नोवा 2 अल्ट्रा 5जी के चुनिंदा वैरिएंट्स 1,000 से 3,000 रुपए तक महँगे होंगे। वहीं, एआई+ नोवाफ्लिप 5जी की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा और यह 49,999 रुपए में उपलब्ध रहेगा। इंडस्ट्री में लागत से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, एआई+ स्मार्टफोन भारतीय ग्राहकों को किफायती कीमतों पर बेहतर अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी आगे भी कंपोनेंट की लागत और बाजार के बदलते हालात पर नजर रखेगी। साथ ही, ग्राहकों को किफायती तकनीक, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक बेहतर वैल्यू देने पर अपना ध्यान बनाए रखेगी।

सेहत और तंदुरुस्ती के क्षेत्र में हुआ विस्तार

प्रयागराज- सेहत और तंदुरुस्ती के क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल एमवे इंडिया ने आज देश के प्रमुख बाजारों में अपने स्टोर्स का दायरा बढ़ाने का एलान किया। यह कदम भारत में कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है और इससे बाजार में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। विस्तार के इस नए दौर की शुरुआत एमवे के प्रेसिडेंट और सीईओ माइकल नेल्सन ने की। अपने आधिकारिक दौरे पर गुरुग्राम पहुंचे नेल्सन ने आज वहां एमवे के नए स्टोर का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले साल 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी, जिसका एक हिस्सा कंपनी के स्टोर्स बढ़ाने पर खर्च होना था। यह विस्तार उसी घोषणा की अगली कड़ी है। इसी के तहत एमवे इंडिया ने प्रयागराज के सिविल लाइन में नया स्टोर खोला, जिससे ग्राहक कंपनी के उत्पादों और ब्रांड को और करीब से जान पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ग्राहकों से मिलने और अपने इलाके में लोगों को जोड़कर समुदाय बनाने के लिए एक समर्पित मंच मिलेगा।

उत्तर प्रदेश ने अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान प्रीमियम अपग्रेड और किफायती शापिंग को अपनाया

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्राहकों और विक्रेताओं की जोरदार भागीदारी देखने को मिली है, जहां स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी, होम और किचन, रोजमर्रा की जरूरतों, ग्रॉसरी और बड़े घरेलू उपकरणों की मांग में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के ग्राहक इस त्योहारी सीजन में प्रीमियम अपग्रेड और किफायती खरीदारी दोनों को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य कारोबारी दिनों की तुलना में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की, जिसमें लैपटॉप, मॉनिटर, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और हेडफोन की मांग शामिल रही। बड़े घरेलू उपकरणों-जैसे रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनरने सामान्य कारोबारी दिनों के मुकाबले वाराणसी में 14 गुना, आगरा और इलाहाबाद में 13 गुना, कानपुर में 11 गुना, मेरठ में 10 गुना और लखनऊ में 9 गुना की वृद्धि दर्ज की। रनिंग शूज में जोरदार मांग देखी गई, जो सामान्य कारोबारी दिनों की तुलना में आगरा, मेरठ और वाराणसी में 6 गुना बढ़ी। अमेज़न बाज़ार पर किफायती खरीदारी सामान्य कारोबारी दिनों के मुकाबले इलाहाबाद और मेरठ में 5 गुना तथा आगरा में 4 गुना बढ़ी। ग्राहक इस त्योहारी सीजन में जारी रहने वाले अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के शानदार ऑफर्स और डील्स का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

आनंद किशोर से ईडी करेगी पूछताछ

पटना (आससे.)। रिशु श्री से जुड़े कथित टेंडर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच एक बार फिर तेज हो गई है. इस मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आनंद किशोर समेत बिहार के छह आईएएस अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. इन अधिकारियों से रिशु श्री जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर पूछताछ की जानी है. जानकारी के मुताबिक, ईडी ने आनंद किशोर, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार, योगेश कुमार सागर, अभिलाषा कुमारी शर्मा और सुनील यादव को समन भेजा है.इन छह आईएएस अधिकारियों में सुनील यादव से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है. वहीं, अभिलाषा कुमारी शर्मा से ईडी की टीम ने कल ही पूछताछ कर चुकी है. अब आनंद किशोर से 30 अक्टूबर को पूछताछ होगी. अधिकारियों से पूछताछ के जरिए ईडी टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े लेनदेन समेत मामले के अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.जानकारी के अनुसार, आनंद किशोर से 30 अक्टूबर को पूछताछ की जानी है. वहीं संतोष कुमार मल्ल से 29 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी. बता दें, ईडी की ओर से जारी समन के बाद सभी अधिकारियों से अलग-अलग समय पर पूछताछ की जाएगी. रिशु श्री से जुड़े इस कथित टेंडर घोटाला मामले में ईडी की जांच पहले भी चलती रही है. इस मामले में 2023 में केस दर्ज हुआ था. अब छह ह्वस अधिकारियों को समन किए जाने के बाद जांच को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, अधिकारियों से पूछताछ में क्या जानकारी सामने आई है, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.उच्च न्यायालय रिशु श्री की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्रिंस एलाइस ने पीएम मोदी से की मुलाकात

नयी दिल्ली (आससे.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस एलॉइस के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत की। प्रिंस एलॉइस की यह भारत की दूसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस एलॉइस और हेरेडिटरी प्रिंसेस सोफी से मुलाकात की थी।इस बीच, शाही जोड़े ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया और आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ह्यविदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजकीय यात्रा के दौरान प्रिंस एलोइस से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति पर प्रकाश डाला।

प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही युवाशक्ति-मुख्यमंत्री

लखनऊ (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। उन्होंने वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार की बदली कार्य संस्कृति से भी प्रदेशवासियों को अवगत कराया और रोजगार सृजन में युवाशक्ति की नई पहचान भी बताई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवाचार की नई सोच हो, उद्यमिता का साहस हो या विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। इसी ऊर्जावान युवाशक्ति के सामर्थ्य, सृजनशीलता और उपलब्धियों का अभिनंदन करने के लिए आज लखनऊ में आयोजित टीओआई यूथ आइकॉन्स समिट एवं अवार्ड्स 2026 में सहभागिता



करूंगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को अवसरों के अभाव में पलायन करना पड़ता था। भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अव्यवस्था से युवाओं का भविष्य अंधकारमय था। प्रतिभा थी, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने इस कार्य-संस्कृति को बदला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी भर्ती, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए आगे बढ़ने के नए अवसर सृजित किए हैं। आज उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति केवल रोजगार की आकांक्षी नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में भी अपनी नई पहचान गढ़ते हुए विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

यूपी : विवादित पोस्ट की भाषा पर चुनाव आयोग ने मांगी माफी

लखनऊ (आससे)। 'राम ने शर्मा को मारा' मामले में आधिकारिक हैंडल से दिये गये जवाब की भाषा को लेकर उठे विवाद के बाद चुनाव आयोग ने माफी मांगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि पोस्ट में इस्तेमाल की गयी टिप्पणियों की भाषा, भाव और तीखापन आधिकारिक हैंडल से अपेक्षित संवाद के अनुरूप नहीं था। नवदीप रिणवा ने कहा कि पोस्ट की टिप्पणियों से लोगों में पैदा हुए वास्तविक आक्रोश को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे अचंभित और नाराज लोगों से ईमानदारी से माफी मांगी जाती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से आधिकारिक हैंडल पर संवाद की भाषा शालीन और औपचारिक रखी जायेगी।

सीबीआईसी ने बदले जीएसटी से जुड़े नियम

नयी दिल्ली (आससे.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी पंजीकरण, कर मांगों और निर्यात भुगतानों पर आठ नए सर्कुलर जारी किए हैं। ये सर्कुलर इस महीने की शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुरूप हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करना और कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।26 अक्टूबर को जारी जीएसटी पंजीकरण दिशानिर्देशों में आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज की सूची शामिल है। इसमें सहमति पत्र, हलफनामे और वचनपत्र के प्रारूप भी दिए गए हैं। इससे कर अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कम होगी। अधिनियम के तहत मांग, अधिनिर्णय और अपील कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण जारी किया है। इसका लक्ष्य अधिकारियों के लिए एक समान संदर्भ ढांचा प्रदान करना है।

पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की कर रहा मदद-सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) और रिटेलर को मिलने वाली कीमतों में भारी अंतर पर सरकार से सवाल किए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद क्यों कर रहा है। कोर्ट ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को निष्क्रिय बताते हुए सवाल किया कि दवाओं की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नजरों के सामने यह सब हो रहा है, क्या इसे ऐसे ही बेलगाम चलने देना चाहिए। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुद्दा ये है कि कई दवाओं की लागत 10-20 रुपए है, यह रिटेलर को 30 रुपए में मिलती है, पर एमआरपी 150-200 रुपए छपा होता है। यही गैप कोर्ट को खटक रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-कैंसर दवाओं का ट्रेड मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित करने पर केंद्र के जवाब को मुश्किल से कुछ खुश होने लायक बताया था। कोर्ट ने सवाल किया था कि सरकार दूसरी दवाओं के ट्रेड मार्जिन की सीमा तय क्यों नहीं कर सकती। अस्पतालों के कैंसर दवाओं पर भारी मुनाफा जोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का सामना कर चुके केंद्र ने कहा था कि उसने एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रूक्रक के 30ब तक सीमित करने का अहम फैसला लिया है। केंद्र के मुताबिक, इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि ?2700 की कैंसर की दवा पर एमआरपी 27,000 क्यों है। कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह नरसंहार है।

एसआईआर : कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी, एक करोड़ नाम कटे

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के मुताबिक, राज्य में अब कुल 4,55,00,011 मतदाता हैं। एसआईआर से पहले यह संख्या 5,54,32,314 थी। इस तरह मतदाता सूची से करीब 99.32 लाख नाम कम हुए हैं। अंतिम सूची में 2,25,40,493 पुरुष और 2,29,12,355 महिला मतदाता हैं। वहीं, तीसरे लिंग के 2,841 मतदाता दर्ज किए गए हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ष की आयु के 6.83 लाख से अधिक मतदाता हैं। बता दें कि 24 अगस्त से 23 सितंबर तक चले दावे और आपत्तियां दर्ज करने के दौरान, मतदाता सूची में 10,08,038 (10.08 लाख) नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,88,324 (1.88 लाख) नाम हटा दिए गए।

मंत्रिमंडल विस्तार से नेकां में असंतोष, उमर के सामने पार्टी एकजुट रखने की चुनौती

जम्मू (आससे.)। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल विस्तार ने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के भीतर मंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं और वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का सवाल फिर खड़ा कर दिया है। चार नए मंत्रियों को शामिल करने और मौजूदा मंत्री सतीश शर्मा को हटाने के फैसले से सरकार का समीकरण बदला है, लेकिन पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर चलना उमर के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ कालू को जगह मिली है। वहीं, वरिष्ठ नेता मुबारक गुल को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से निराशा की खबर सामने आई है। इससे पार्टी में वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के करीबी नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर सवाल उठने की गुंजाइश बढ़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही मंत्री पद के दावेदार विधायकों की संख्या और नेतृत्व पर दबाव की खबरें सामने आ रही थीं। उमर ने सार्वजनिक रूप से विधायकों से मंत्री पद के लिए उन्हें और पार्टी अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला को संदेश भेजना बंद करने की अपील की थी। यह संकेत था कि सीमित पदों के मुकाबले पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या कहीं अधिक है। नेकां के लिए चुनौती केवल असंतुष्ट नेताओं को मनाने तक सीमित नहीं है। सरकार को चुनावी वादों, बेरोजगारी और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने जैसे मुद्दों पर भी जवाब देना है। कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल होने तक मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर चुकी है, जिससे गठबंधन की राजनीति भी जटिल बनी हुई है। पार्टी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उमर असंतोष को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक सीमित रख पाते हैं या यह नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया पर व्यापक सवाल बन जाता है। यदि वरिष्ठ नेताओं और उपेक्षित विधायकों में नाराजगी बनी रहती है, तो उसका असर विधानसभा में पार्टी के तालमेल, सरकार की कार्यक्षमता और भविष्य की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। फिलहाल, असंतोष के व्यापक संगठनात्मक संकट में बदलने की पुष्टि नहीं हुई है।

खड़गे ने १३ राज्यों की जारी कर दी लिस्ट

नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एसआईआर को लेकर एक आंकड़ा जारी कर केंद्र और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर 1 नवंबर को प्रस्तावित विपक्ष की रैली को दबाने का भी आरोप लगाया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि इंडिया गठबंधन हर नागरिक के वोट और हमारे संविधान की रक्षा के लिए अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा. कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक समेत 13 राज्यों में हुए एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जैसे-जैसे चुनाव आयोग के कारनामे सामने आ रहे हैं और वोट चोरी का पर्दाफाश हो रहा है, मोदी-शाह जन-आंदोलन को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं! वे सीईसी ज्ञानेश कुमार को क्यों बचा रहे हैं. ध्यान भटकाने की ये चालें और झूठा प्रचार केवल मोदी सरकार की साख गिरा रहे हैं और हमारे लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं.उत्तर प्रदेश: पीलीभीत में 10,470 अनियमित फॉर्म 8 बदलावों के कारण एफआईआर दर्ज की गई और राज्यव्यापी ऑडिट शुरू हुआ. अलग से 158 एमएलसी इलेक्टोरल रोल एंट्री में सॉफ्टवेयर-जनरेटेड नाम की गलतियां थीं. महाराष्ट्र: एसआईआर ड्राफ्ट रोल से 2.07 करोड़ नाम हटा दिए गए. एमएलसी सूचियों में कंप्यूटर/ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन की वजह से हुई गलतियां सामने आईं.पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनावों के बाद मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की तय की गई अपीलों में से 93 फीसदी सफल रहीं.राजस्थान: भारतीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की सूचियों के बीच लगभग 30 लाख विसंगतियां पाए गए.गुजरात: एसआईआर के बाद मतदाता सूची में 68.12 लाख नाम घट गए. अब लोगों के नाम फिर से जोड़ने का खास अभियान चलाया जा रहा है.कर्नाटक: आम तौर पर फॉर्म 7 कोई आम नागरिक या मतदाता किसी का नाम कटवाने के लिए भरता है, लेकिन यहां खुद चुनाव अधिकारियों द्वारा ही 61,059 लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरे गए, जिस पर सवाल उठाए गए हैं। आंध्र प्रदेश: 20,959 फॉर्म 7 आवेदनों में चुनाव अधिकारियों को ही आपत्ति जताने वाले के रूप में नामित किया गया। झारखंड: चतरा विधानसभा क्षेत्र में 4,790 फॉर्म-7 आवेदन आए, जो राज्य के कुल आवेदनों का लगभग 36 फीसदी है. दिल्ली: ड्राफ्ट रोल से 47.5 लाख नाम हटा दिए गए. मीडिया जांच के बाद फॉर्म-6 के निपटान आंकड़ों को संशोधित किया गया।

हूतियों के आगे सऊदी का सरेंडर

हूतियों के साथ विवाद का एक हिस्सा तीन साल पहले बनी सहमतियों को लागू करने से जुड़ा है

रियाद (एजेंसी)। इजरायली मीडिया ने खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ने यमन के हूती ग्रुप को 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है। यह पेशकश ईरान की मध्यस्थता में हुए एक समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद सीजफायर लागू करना और सऊदी अरब पर हो रहे हमलों को रोकना है। रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान हूतियों के साथ सीजफायर पर बातचीत करने के लिए तेहरान गए थे। इस प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान के माध्यम से हूती समूह को 1 अरब अमेरिकी डॉलर दिए जाने की बात है।

एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि सऊदी के मंत्री उस हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान में ही यह रकम लेकर आए थे, जिससे वे तेहरान पहुंचे थे। हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोई रकम ट्रांसफर की गई है या नहीं। खबरों के मुताबिक, इस बातचीत में तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। इनके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, सुप्रीम



नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव मोहसेन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल प्रतिष्ठानों पर बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने सऊदी अरब और हूतियों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। इन हमलों से सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर हुए ईरानी हमलों की वजह से खाड़ी क्षेत्र से तेल के निर्यात में भी बाधा आई है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में इस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की तेहरान यात्रा, इस गठबंधन के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनका मकसद मौजूदा संकट में शामिल पक्षों के बीच तनाव कम करना, बातचीत और राजनयिक समाधान को बढ़ावा देना, तथा कतर और पाकिस्तान द्वारा की जा रही मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करना है। इजरायली मीडिया से बात करते हुए एक सऊदी अधिकारी ने पैसों के लेन-देन की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि हूतियों के साथ विवाद का एक हिस्सा तीन साल पहले बनी सहमतियों को लागू करने से जुड़ा है। इन समझौतों के तहत, सऊदी अरब को हुतियों को सीधे आर्थिक मदद देनी थी, ताकि विवाद को सुलझाने की कोशिशें आगे बढ़ सकें। इस फंडिंग का मकसद, अन्य बातों के अलावा, हुतियों के नियंत्रण वाले इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना और आम नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना था। रिपोर्टों के अनुसार, इसके बदले में हुतियों से यह उम्मीद की गई थी कि वे सीजफायर का पालन

पृष्ठ एक का शेष

वाराणसीके...

चितईपुर और टांस वरुणाके पुराने वार्डको लेकर २६ वार्डोंमें पेयजल और सीवर लाइन बिछानेका कार्य किया जायेगा। जिसमें करीब २६७८.९२ करोड़ खर्च होनेकी सम्भावना है। कैबिनेटसे इन प्रस्तावोंके स्वीकृत होनेके बाद संबंधित विभागोंने कागजी प्रक्रिया तेज कर दी। इन क्षेत्रोंमें टेण्डर आमंत्रित धरातलपर निर्माण कार्य शुरू कराये जायेंगे। जिससे नागरिकोंको गन्दगीसे मुक्ति मिलेगी। २२ वार्डोंमें अमृत दो योजनाके तहत २१६१ करोड़की लागतसे ३५३.१३ किलोमीटर सीवर लाइन और ६५१.६४ किलोमीटर पेयजल लाइन बिछानेको मंजूरी मिली है। जिन तीन वार्डोंमें ये लाइनें बिछायी जायेगी उनमें चितईपुरके अन्तर्गत भगवानपुर, छित्तूपुर खास, सीवरगोवर्धन, सुसुवाहीं, कंदवा और करौंदी। यहां के लिए कैबिनेटने पेयजल योजनापर २२७.९० करोड़, सीवर योजनापर ७४८.९० करोड़, इसी प्रकार लहरतारा जोनमें मंडुवाडीह, फुलवरिया, शिवदासपुर, लोहता, मढ़ौली, ककरमत्ताके लिए बजट स्वीकृत किया गया है जिसमें पेयजल योजनापर २१४.२१ करोड़, सीवर योजनापर ६३०.६४ करोड़ और वरुणा जोनमें पुराने वार्ड नम्बर १३ में सरसौली, तरना, पाण्डेयपुर, नारायणपुर, दनियालपुर, अकथा, सारनाथ, पहड़िया, खजुरी, रमरेपुर, ढिढोरी महाल, सिकरौल और शिवपुरमें पेयजल योजनापर २५२.८५ करोड़ और सीवर योजनापर ६०४.४२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

104.28..

केंद्र (उप्र-सीएसओसी) की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस केंद्र के जरिये प्रदेश के डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सरकारी ऐप्लीकेशन और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्तियों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि, हमले या डेटा सेंधमारी की स्थिति में त्वरित काररवाई और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यूपी : विधान परिषद...

शुरुआती बढ़त बनाए हुए हैं। इन सभी 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 152 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मतपत्रों के बंडल बनाने और मतपत्रों की संख्या के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। लखनऊ में मतगणना केंद्र पर शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान शाम करीब 4.30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर विवाद की स्थिति बन गयी। इसी प्रकार स्नातक सीट की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की कांति सिंह ने मतपत्रों की संख्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने एक्स कर लिखा है कि आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब प्रशासन द्वारा काउंटिंग रोके जाने की सूचना है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो। इन आरोपों पर एडीएम आगरा यमुनाधर चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि काउंटिंग रोकी नहीं गयी है और यथावत जारी है।

रामलीला...

से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की बुकिंग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था और अनुमति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, अशोक होटल में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने कहा कि यह निजी परिसर है और अनुमति का फैसला होटल प्रबंधन पर निर्भर करता है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए विपक्ष के अभियान में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखेगा। उनके मुताबिक, एक नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में करीब 21 विपक्षी दल शामिल होंगे। जगह को लेकर अड़चन आने पर गठबंधन दूसरे स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करेगा।

ज्ञानेशके...

जवाब मांगे जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा क